The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com

अध्यापक शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव

अमित कुमार शुक्ल

अतिथि प्रवक्ता
बी.एड.विभाग
एमएलके पीजी कॉलेज, बलरामपुर

सारांश-

शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। शिक्षा देने का दायित्व समाज ने अध्यापकों पर छोड़ रखा है इस लिए अध्यापक शिक्षा की चर्चा करना आवश्यक है। भारत में अध्यापक शिक्षा की जड़ें बहुत गहरी हैं किंतु अध्यापक शिक्षा का वर्तमान ढांचा 19वीं सदी के मध्य तैयार हुआ। प्राचीन काल में अध्यापक एवं अध्यापन कार्य एक व्यवसाय मात्र न होकर एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। संपूर्ण शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी औऱ छात्रों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना होता था।

प्राचीन तथा मध्य काल में अध्यापन योग्यता को एक जन्मजात या प्रकृति प्रदत योग्यता स्वीकार किया जाता था। उस समय की मान्यता थी कि अध्यापक बनने वाला व्यक्ति जन्म से ही अध्यापन संबंधी प्रतिभा से संपन्न होता है, उसे किसी भी प्रकार के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती । अर्थात उस समय की मान्यता थी कि अध्यापक जन्मजात होते हैं न कि निर्मित किए जाते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विश्व के लगभग सभी देशों में अध्यापक के जन्मजात होने संबंधी मान्यता का खंडन किया जाने लगा तथा धीरे-धीरे सभी देशों में स्वीकार किया जाने लगा कि प्रशिक्षण देकर श्रेष्ठ सुयोग्य अध्यापक तैयार किए जा सकते हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो अध्यापकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा। पहले विषय वस्तु में निपुणता ही अध्यापक बनने के लिए आवश्यक थी, परंतु बाद में शिक्षण योग्यता को भी आवश्यक माना जाने लगा । वास्तव में बाल मनोविज्ञान तथा अध्यापन विज्ञान के विकास के साथ-साथ अध्यापकों के संबंध में पुरानी धारणा परिवर्तित होने लगी तथा ज्ञानार्जन व ज्ञान प्रदान करने की योग्यता को भिन्न-भिन्न स्वीकार किया जाने लगा ।अब यह स्वीकार करना गलत होगा कि विषय विशेष में निपुण व्यक्ति उस विषय का शिक्षण भी प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। अब शिक्षण को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसको करने के लिए शिक्षण कला का सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अभ्यास आवश्यक है। किंतु अगर अध्यापक शिक्षा की ओर हम दृष्टिपात करें तो धूप -छांव दोनों का एक चित्र हमारे सामने आता है अर्थात एक तरफ अध्यापक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ गुणात्मकता का हास हुआ है। आज आजादी के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं कमजोरी आई है तो वह है, शिक्षा का क्षेत्र ! और शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापक शिक्षा। निजी करण की आंधी का सबसे बुरा असर अध्यापक शिक्षा पर पड़ा है। जिस तरह से अध्यापक शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है वह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। इस शोधपत्र में अध्यापक शिक्षा का निजीकरण एवं उसके प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों, शिक्षक- शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की धुरी शिक्षक ही होता है। शिक्षक के निर्देशन के अभाव में शिक्षार्थी सही ढंग से ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ, महान और उत्तम क्यों न हो, पाठ्यक्रम कितना भी समाज उपयोगी अग्रदर्शी, जनतंत्रीय, लचीला और व्यापक क्यों न हो, शिक्षण विधियां कितनी भी मनोवैज्ञानिक और छात्रोपयोगी क्यों न हो, शिक्षण सामग्री कितनी भी प्रभावशाली और रुचिपूर्ण क्यों न हो, भौतिक सुविधाएं कितनी भी क्यों न उपलब्ध हों, यदि शिक्षक प्रभावशाली नहीं है ,वह अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने विषय में और कार्य में रुचि नहीं है, और उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, तो वह छात्रों में उस भावना का विकास नहीं कर सकता जिसकी समाज को आवश्यकता है। एक योग्य शिक्षक ही अपने कार्य एवं व्यवहार तथा व्यक्तित्व के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। किंतु क्या हम आज योग्य शिक्षकों का निर्माण कर पा रहे हैं मुझे तो कदाचित इसमें सन्देह है ? योग्य शिक्षक तो दूर हम साधारण शिक्षकों का भी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं।

आज प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर हैं, और उच्च शिक्षा के कंगूरे बेदम दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कहीं न कहीं अध्यापक जिम्मेदार है। हम आज जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं ,हम इस बात को जान रहे हैं कि कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है । किंतु क्या हमारी सरकारें योग्य अध्यापकों के निर्माण के लिए तत्पर हैं। जिस देश में अध्यापक शिक्षा के लगभग 90% शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान निजी हाथों में हों, उन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई नीति न हो, निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो, निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षकों का खुद का कोई भविष्य सुरक्षित न हो। और सरकार यह कह रही है कि योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार कर रहे हैं। आज देश के अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थान प्रशिक्षक विहीन हैं और अगर प्रशिक्षक हैं भी तो वह कागज पर हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार कौन कर रहा है, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आज अगर शिक्षा अपने उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही है तो उसके लिए अध्यापक शिक्षा जिम्मेदार है । आज अधिकांश शिक्षक- शिक्षा संस्थाएं अपनी दिशा भटक गई हैं और यही कारण है कि आज समाज में ऐसे योग शिक्षकों का अकाल सा पड़ गया है, जो अपने आकर्षक व्यक्तित्व से समाज को दिशा निर्देश देने की सामर्थ्य रखता हो, जिससे समाज अपने बच्चे के भविष्य को उसके हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो सके। आज के युवा और बाल वर्ग कल के नागरिक होंगे, और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण समाज में मानवीय गुणों से युक्त एवं नागरिकता के दायित्वों का निर्वहन करने वाले निष्ठावान व्यक्तियों की संख्या में कमी आती जा रही है, जिससे समाज में आदर्श रिक्तता, ज्ञान शून्यता, चरित्र हीनता, भ्रष्टाचार राजनीतिक अपराधीकरण, आदि बढ़ता जा रहा है और सरकार इस मूल समस्या का समाधान खोजने का प्रयास नहीं कर रही है । समाज में जिस तरह से मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है उसके लिए कहीं न कहीं अध्यापक शिक्षा का निजीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

आज अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के कारण सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय नहीं रह गया है। शिक्षक शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय की कड़ी है। सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय होना आवश्यक है निजी अध्यापक शिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे शिक्षकों के बूढ़े हुए माता-पिता की दवाई ,बड़े हुए बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता शिक्षक को भी है। क्या सरकार ने अध्यापक शिक्षा के निजीकरण करते

समय उनमें कार्यरत प्रशिक्षकों के बारे में सोचा, जवाब मिलेगा नहीं। इससे अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रभावित होता है और अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रभावित होने का सीधा असर समाज के बच्चों पर पड़ता है उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यदि शिक्षक शिक्षा के निजीकरण के साथ इस समस्या में सुधार के लिए कठोर कदम नहीं उठाया गया तो यह देश के लिए घातक होगा। शिक्षक सामान्य नहीं होते उनकी गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं, इसलिए शिक्षकों के निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता है ।यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या और सबको शिक्षा सुलभ कराने के लिए अधिक से अधिक अध्यापकों की आवश्यकता से इंकार नही किया जा सकता जो अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के बिना संभव भी नहीं है।इसलिए निजी करण के साथ-साथ उस पर सरकार का भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कार्यरत अध्यापकों के संबंध में भी सरकार को सोचना होगा तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक समाज को मिल सकते हैं ।

विषय वस्तु

वैदिक काल से अध्यापन कार्य एक अध्यात्मिक कार्य माना जाता था। उस काल में कक्षा नायकीय पद्धति प्रचलित थी। इस व्यवस्था से कक्षा नायकों में ज्ञान की गहराई आती थी और उनका प्रशिक्षण भी हो जाता था। कक्षा नायक अध्यापन में प्राया अपने गुरु की प्रणाली का ही अनुसरण करते थे। इस प्रणाली के द्वारा ही प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। मध्य काल में भी शिक्षकों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। प्राया मौलवी ही शिक्षण कार्य वंश परंपरा के आधार पर करते थे। अध्यापक प्रशिक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं था। कक्षा नायक की प्रणाली इस काल में भी प्रचलित थी। बड़ी कक्षा के योग्य छात्र छोटी कक्षाओं के छात्रों को अपने गुरु के पद्धति के आधार पर पढ़ाते थे।

आधुनिक अर्थों में शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश काल में ही हुआ। इस काल में अध्यापकार्य एक वृति के रूप में विकसित होने लगा। अतः अध्यापन में प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। सर्वप्रथम 1819 में कोलकाता स्कूल सोसाइटी ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की । इसके बाद 1824 में मुंबई में देसी विद्यालय समाज ने तथा 1826 में मद्रास शिक्षा समाज की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए गए। सन 1856 में इसे गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल मद्रास के रूप में विकसित किया गया जो सन 1886 में अध्यापक प्रशिक्षण कालेज के रूप में विकसित हो गया । "सन 1854 में वुड के घोषणा पत्र में तथा 1859 में लॉर्ड स्टैनले के घोषणा पत्र में भारत के प्रत्येक प्रांत में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर बल दिया गया। सन 1882 तक भारत में कुल 106 नॉर्मल

स्कूल थे जिनमें 3886 छात्राध्यापक नामांकित थे। माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी थी सन 1882 तक केवल 2 प्रशिक्षण विद्यालय, एक चेन्नई में और दूसरा लाहौर में था। सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग(हंटर कमीशन)ने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में अनेक सुझाव दिए।19 वीं शताब्दी के अंत तक देश में बहुत सारे नॉर्मल स्कूल स्थापित हो चुके थे। इसके अतिरिक्त 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

सन 1904 में लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति, 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, तथा 1929 में हरट्रांग समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक महत्व दिया और उसके विस्तार एवं सुधार के सुझाव दिए । इस अवधि में देश में नॉर्मल स्कूलों की संख्या 1072 थी जिनमें 27000 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई। 1936 में

मुंबई विश्वविद्यालय ने एम०एड०का कोर्स प्रारम्भ किया। सन् 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट में भी शिक्षक -प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए"|.....(1)

स्वतंत्र भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षक शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में शिक्षक शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक शिक्षा के विस्तार गुणवत्ता सुधार और धनराशि के आमंत्रण में उदारता बरती गई है। महिलाओं के लिए शिक्षण सुविधाओं के विस्तार को वरीयता दी गई है तथा उनके लिए पृथक दीक्षा विद्यालय खोले गए।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का पता लगता है। कहा गया कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले।

आज हमें अगर अपने देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण से तैयार शिक्षक जो विद्यालयों में शिक्षण करने के लिए जाते हैं उनका संबंध सीधा छात्रों से होता है।जिस तरह से वे प्रशिक्षण प्राप्त किए रहेंगे उसी प्रकार के छात्रों को शिक्षित कर पाएंगे ।यह निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को भी ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण से कोई समझौता न किया जाय।

अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के बावजूद विकास के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के स्थान तथा महत्व को भी आज हम अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं । यदि गुणवत्ता नियंत्रण को महत्व नहीं दिया जाता है तो पारंपरिक प्रत्यक्ष माध्यम से जो कि औपचारिक रूप से प्रचलित है उत्तम स्तरीय अध्यापक प्रस्तुत करने में प्राया: असफल साबित होते रहेंगे। एन सी टी ई में भी आज जो भ्रष्टाचार व्यापक रूप से पनप रहा है उसके चलते अनेक ऐसे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त कर चुके हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तो दूर एक साधारण शिक्षक भी तैयार करने की क्षमता नहीं रखते हैं"।----------02

देश के बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में शिक्षा मि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके लिए शिक्षा के दोनों संसाधनों को (भौतिक और मानवीय) शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। यदि मानवीय संसाधन सही नहीं हैं तो भौतिक संसाधन कितना भी अच्छा क्यों न हो, कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों की नैतिकता और निष्पक्षता ही उसे उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाने में असमर्थ होती है आज अध्यापक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिक चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना है तभी राष्ट्र मानवीय संसाधनों से संपन्न हो सकता है और ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है।

उपसंहार-

किसी भी अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह उन बालकों को अच्छी तरह से समझता हो जिन्हें वह पढ़ा रहा है। शिक्षा को बाल केंद्रित मानने के कारण यह आवश्यक है, कि अध्यापक विषय वस्तु के साथ-साथ बालकों की प्रकृति को भी अच्छी तरह से समझे। विभिन्न आयु वर्गों के बालकों में विकास व वृद्धि किस प्रकार से होती है, बालकों की आवश्यकताएं क्या है ,बालक किस प्रकार से सीखते हैं, बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है, बालकों में वांछित अभिवृत्ति व मूल्य कैसे विकसित किए जा सकते हैं, बालकों के संवेगों को कैसे नियंत्रित, परिवर्तित व संशोधित किया जा सकता है बालकों में हीन ग्रंथियों के विकास पर कैसे

अंकुश लगाया जा सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है ,जैसे अनेक प्रश्नों का उत्तर बाल मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उपरांत ही जान जा सकता है। एक शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक इन प्रश्नों का उत्तर खोज कर बालक के विकास की सरलता व सुगमता तथा द्रुत गति से संभव बना सकता है जबकि एक अप्रशिक्षित अध्यापक मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भली-भांति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।

" शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा शिक्षण को रोचक जीवन्त व प्रभावशाली बनाने में समर्थ होता है वह मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य व पुष्ट शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके अपने छात्रों को सहजता, सरलता व सुगमता से स्थाई ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत एक अप्रशिक्षित अध्यापक अपने शिक्षण को नीरस के कृतिम व अरुचि पूर्ण ढंग से सम्पन्न करके छात्रों को शिक्षा के प्रति विरक्त कर देता है। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रशिक्षण को जीवंत बना देता है।

एक अच्छे अध्यापक के लिए न केवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना आवश्यक है वरन उसे अध्यापक के रूप में अन्य अनेक दायित्वों का पालन करना होता है परीक्षा व मूल्यांकन, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन,पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, समाज में शिक्षा की महत्ता की स्थापना जैसे कार्य भी अध्यापकों को करने होते हैं। इसके लिए शिक्षा के उद्देश्यों व राष्ट्र निर्माण में योगदान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों मूल्यांकन विधियों, प्रशासन की तकनीकों आदि का ज्ञान भी अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। उपरोक्त बातों का विशद ज्ञान व अभ्यास शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाता है ।अध्यापक शिक्षा प्राप्त करके ही वे अपने गुरुतर दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो सकेंगे"।----------3

आज समय की मांग है कि हमें ऐसी शिक्षक- प्रशिक्षण की व्यवस्था का निर्माण करना होगा जो भारत में प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की मांग को पूरा कर सके और साथ ही साथ इस व्यवस्था में निर्धन एवं विशाल भारतीय समुदाय की प्रमुख सीमाओं का ध्यान रखा जाए। शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएं सिद्धांतों को अधिक से अधिक व्यावहारिक रूप प्रदान करने की ओर अग्रसर हो,यह बातें निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में भी लागू हो और सरकार इसका निरीक्षण कराए।

निष्कर्ष एवं सुझाव---

आज यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि अध्यापन व्यवसाय में सफलता के लिए अन्य व्यवसायों से अधिक कुशलता की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि अध्यापक का प्रत्यक्ष संबंध समाज के सबसे मूल्यवान परंतु कोमल निधि बालक से होती है। इस व्यवसायिक कुशलता को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। परंतु अब तक हमारे देश में अध्यापक प्रशिक्षण की समस्या को संख्यात्मक रूप में ही स्वीकार किया गया है,और निजी शिक्षक -प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देकर केवल प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में ही कार्य हुआ है।प्रशिक्षण के स्तर को प्रभावी बनाने के लिए और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया।जो देश के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है।

निजीकरण का अध्यापक शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि यह सत्य है, कि बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है,जो केवल सरकारी शिक्षक -प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जितना आवश्यक है,उतना ही निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानो पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे वे उद्योग बनने से बचें। अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के बाद यह एक प्रकार से उद्योग बन गया है जहां केवल प्रवेश और परीक्षाये हो रही हैं।किसी शिक्षक- प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश ले लेने मात्र से कोई योग्य अध्यापक नहीं बन जाता है जब तक उसे सही ढंग से योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षित न किया जाए। अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के संबंध में निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है|

1- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से अध्यापक बनना बहुत महंगा हो गया है जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के गरीब किन्तु मेधावी बच्चों की अध्यापक बनने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है।

2- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों का शोषण होने की संभावना बनी रहती है जिससे प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से कुछ निजी लोगों का ही लाभ हो रहा है। केवल प्रवेश और परीक्षा दो ही कार्य हो रहे हैं। प्रशिक्षण सही ढंग से न होने से देश के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

4- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से देश में शिक्षक- प्रशिक्षण संस्थानों की केवल संख्यात्मक वृद्धि हो रही है गुणात्मक नहीं।

5- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी जा रही है ,जिससे समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है।

6- अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ी है।भ्रष्टाचारियों द्वारा अध्यापक शिक्षण संस्थानों को भी अपने जाल में फंसा लेने की संभावना बलवती हुई है।

ऐसी स्थिति में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं

सुझाव--

अध्यापक शिक्षा के निजीकरण के बाद होने वाली समस्याओं के समाधान में निम्नलिखित सुझाव मेरे समझ से प्रासंगिक प्रतीत होते हैं--

1.अध्यापक शिक्षा के निजीकरण होने पर भी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए जिससे निजी अध्यापक शिक्षण संस्थान मनमानी न सकें। साथ ही साथ गरीब किन्तु मेधावी छात्र छात्राएं जो अध्यापक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं उनको सरकार वित्तीय सहयोग दें।

2. अध्यापक शिक्षा की निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के शोषण के संबंध में सरकार कोई नीति बनाए जिससे शुल्क का अधिकांश पैसा प्राध्यापकों को वेतन के रूप में दिया जा सके।

3. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समय-समय पर सरकार को इसका औचक निरीक्षण कराना चाहिए।

4.शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए न कि केवल संख्यात्मक बुद्धि पर ध्यान दें।

5. शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थानों में सुधार करके शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है जिससे समाज में योग्य शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।

6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को सरकार द्वारा रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। जिससे योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक समाज को मिल सके और समाज का विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची—

1.डॉ.सारस्वत मालती ---भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं |

2. डॉ.भट्टाचार्य सी.जी.---"अध्यापक शिक्षा "विनोद पुस्तक भवन आगरा |

3. डॉ.गुप्ता एल.पी.-------भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं |

4.डॉ.पचौरी गिरीश ------उद्दीयमान भारतीय समाज में शिक्षक |

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-April-2023/33

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

अमित कुमार शुक्ल

for publication of research paper title

अध्यापक शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-01, Month April, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com